



सदियों से क्रोएशिया, बॉस्निया और हर्जगोविना की औरतें अपनी बेटियों के शरीर पर गोदना गोदती रही हैं। इस प्राचीन परंपरा को "सिकाच्यो" कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है, सुई चुभाना। शहद, कालिख, थूक और दूध (ब्रेस्टमिल्क) के मिश्रण में सुई डुबोकर हाथ, छाती और कभी-कभी माथे पर डिजाइन बनाए जाते थे। 1920 के दशक में मानवविज्ञानी ईडिथ डरहम ने लिखा था कि, 4000 सालों तक "सिकाच्यो" की परम्परा महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रही। लेकिन 20 वीं सदी के मध्य में यह परम्परा लुप्त हो गई। तथापि, अब बाल्कन महिलाओं व पुरुषों की नई पीढ़ी अपनी विरासत को पुनः पहचान देने के लिए इस परम्परा को पुनर्जीवित कर रही हैं। यह तो पता नहीं है कि, कांस्य युग के इन आदिवासियों में टैटू बनाने की परम्परा कब और क्यों शुरू हुई, पर शायद इसका सम्बंध धर्म या सामाजिक स्तर से रहा होगा। सिकाच्यो प्रोजेक्ट की सहलेखक मारिया मरैसिक कहती हैं, "दुर्भाग्यवश हमारे पास इस परम्परा की आधुनिक स्रोत नहीं हैं।" बॉस्निया में जन्मी मारिया मरैसिक ने अमेरिका की क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि, प्राचीन यूनानियों ने अपने लिखित इतिहास, गुलदस्तों व अन्य कलाकृतियों पर बाल्कन लोगों को टैटू के साथ चित्रित किया था। पुराविदों को 3000 साल पुराने मकबूरों से तांबे की सुइयों मिली हैं जो टैटू बनाने के काम आती थीं। कुछ प्राचीन डिजाइन तो बहुत आम थे, जैसे कोलो सर्किल, जो परिवार की एकता का प्रतीक था। इसी नाम का एक पारम्परिक नृत्य आज भी इन क्षेत्रों की शादियों व अन्य समारोहों में किया जाता है। गांव व जाति के प्रतीक के रूप में भी टैटू बनते थे। असल में सिकाच्यो का सम्बंध पहचान के साथ साथ, सुरक्षा, आशीर्वाद व सौंदर्य से भी रहा है। पंद्रहवीं सदी में इसमें परिवर्तन आया। महिलाएं अपने बेटों के शरीर पर टैटू बनाने लगीं। ऑटोमन के राज में ईसाई बाल्कन परिवारों से टैटू वसूल जाता था, जिसके तहत आठ साल के लड़कों को इस्ताम्बूल ले जाया जाता था जहां वे राजा के आसपास रहते थे। हालांकि बड़े होकर ये बच्चे उच्च पदस्थ सैनिक व अधिकारी बनते थे, लेकिन घर से फिर भी बहुत दूर थे। इसलिए माताएं अपने लड़कों के शरीर पर भी टैटू बनाने लगीं, क्योंकि, बच्चे जब लौटते थे तो परिवार उन्हें पहचान लेता था। बीसवीं सदी में सोशलिस्ट फैंडरल रिपब्लिक युगोस्लाविया के काल में यह परम्परा खत्म होने लगी, महिलाओं ने अपने टैटू छिपाना शुरू कर दिया और लड़कियों ने टैटू बनवाने से मना कर दिया।

'पांच फीसदी लोगों का देश की 60 फीसदी संपत्ति पर कब्जा हो गया है'

कांग्रेस ने कहा कि, देश के प्रति व्यक्ति कर्म में ढाई गुना का इजाफा हुआ है

नई दिल्ली 22 जनवरी (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां अरबपतियों की आय बढ़ाने और जनसामान्य की आय घटाने का काम कर रही है जिससे देश में आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हो रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लव ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रति व्यक्ति आय घट रही है और महज 5 फीसदी लोगों का देश की 60 फीसदी संपत्ति पर कब्जा हो गया है और प्रति व्यक्ति कर्म ढाई गुना कार इजाफा हुआ है।

उन्होंने कहा कि आश्रय की बात यह है कि जिन लोगों के पास 60 फीसदी संपत्ति है उनका देश के जी.एस.टी. में योगदान महज तीन प्रतिशत है और जिन

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लव ने कहा कि आश्रय की बात यह है कि, जिन लोगों के पास 60 फीसदी संपत्ति है उनका देश के जीएसटी में योगदान महज तीन प्रतिशत है और जिन लोगों के पास देश की महज तीन फीसदी संपत्ति है उनका जीएसटी में योगदान से अधिक है।

लोगों के पास देश की महज तीन फीसदी संपत्ति है उनका जी.एस.टी. में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है।

प्रवक्ता ने कहा कि 2014 में मोदी साबन ने जब सत्ता संभाली तो देश में कर्म बंद कर दिया था जो अब बसकर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

सवाल है पिछले नौ साल में कर्म ढाई गुना कैसे बढ़ा है। उनका कहना था कि देश के हर नागरिक पर एक लाख से

ज्यादा कर्म हो गया है लेकिन उसका फायदा सबको नहीं बल्कि देश के 5 प्रतिशत अमीरों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में सबका आर्थिक विकास होना चाहिए था लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कुछ ही अरबपतियों को फायदा हो रहा है और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ रही है जबकि संपत्ति उन लोगों की बढ़ने चाहिए थी जो जी.डी.पी. में योगदान दे रहे हैं लेकिन उन लोगों पर कर्म बढ़ रहा है।

उपेन्द्र कुशवाहा ने जे.डी.यू. छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज किया

नई दिल्ली, 22 जनवरी। बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से बड़ी ही हलचल मची हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रहे जे.डी.यू. संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जे.डी.यू. छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों पर अब खुद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "बीजेपी के नेताओं से मिलने का मतलब यह नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूँ। ये सब निराधार अफवाहें हैं। मैं उनसे अस्पताल में मिला, इसका राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। मैं जे.डी.यू. में हूँ, जे.डी.यू. कमजोर हो रही है लेकिन मैं इसे मजबूत

कुशवाहा ने कहा कि, मेरा भाजपा में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

करने के लिए काम करता रहांगा।" उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पार्टी में आते-जाते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ-साफ लगा कि जे.डी.यू. और उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। कुशवाहा की जे.डी.यू. से दूरी का संकेत नीतीश कुमार के बयान से लगाया जा सकता है। नीतीश से जब

कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह कर चौका दिया कि वो आते-जाते रहते हैं। अब आपको वो वजह बताते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के जे.डी.यू. छोड़ने का फैसला हो सकते हैं। कुशवाहा जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी आर.एस.एल.पी. का जे.डी.यू. में विलय किया तो उन्हें जे.डी.यू. संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संगठन में उनकी ज्यादा चलती नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि वो बिहार की महागठबंधन सरकार में डिप्टी सी.एम. या मंत्री पद चाहते थे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया।

'सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कई लोगों, खासकर युवाओं की मदद करेगा।

"प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "भारत में कई भाषाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता में इजाफा करती हैं। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प शामिल है।"

'न्यायपालिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संविधान के लिए विदेशी बताया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एन.जे.ए.सी.) और एक संबंधित संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत पर सवाल उठाया है।

राष्ट्रपति जो बाइडन के घर पर एफ.बी.आई. ने फिर से छाप मारा

13 घंटे तक तलाशी चली, एफ.बी.आई. ने बाइडन के घर से कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किये हैं

वाशिंगटन, 22 जनवरी। अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी एफबीआई ने एक बार फिर राष्ट्रपति जो. बाइडन के विलमिंटन स्थित आवास की तलाशी ली है। इस दौरान गोपनीय दस्तावेज के तौर पर उनके कार्यकाल के समय के छह और गोपनीय दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों का मिलना बाइडन के लिए ऐसे समय में राजनीतिक जवाबदेही बन गया है, जब वह फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यह घटना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उतार-चढ़ाव भरे कार्यकाल के बाद अपने कार्यकाल को अमेरिकी जनता के सामने बेहतर दिखाने की बाइडन की कोशिश को नुकसान पहुंचाती है। बाइडर ने शनिवार को बताया कि एफ.बी.आई. ने शुक्रवार को जिन दस्तावेजों को कब्जे

विप्रे ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए आकलन शामिल है। यह व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। बयान में कहा गया है कि हमें 452 फ्रेसर्स को बाहर करना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण के बाद भी बार-बार असेसमेंट में खराब प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अनुसार, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को सूचित किया कि वे प्रत्येक प्रशिक्षण लागत के लिए 75,000 रुपये का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी ने खर्च को "भाफ" कर दिया है। बताते चलें कि पिछले हफ्ते, कंपनी ने दिसंबर 2022 तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में उम्मीद से बेहतर 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चौथी तिमाही के लिए "मजबूत" बुकिंग के बारे में आशा व्यक्त की है।

इन दस्तावेजों का मिलना बाइडन के लिए ऐसे समय में राजनीतिक जवाबदेही बन गया है, जब वे फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।

इससे बाइडन की छवि को भारी नुकसान पहुंचने की पूरी-पूरी संभावना है।

में लिया है, वे बाइडन के सीनेटर एवं उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल से संबंधित हैं, जबकि नोट उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के हैं। उन्होंने कहा कि यह तलाशी करीब 13 घंटे तक चली। बाइडर ने बताया कि अभी न्याय विभाग ने रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दस्तावेजों की गोपनीयता का क्या स्तर है

हाड़ौती कांग्रेस में अंतर्द्वंद, भाया समर्थक विधायकों ने भरत सिंह को बताया जयचंद

विधायक मेघवाल और सहरिया ने कहा, "हाड़ौती में पार्टी को कमजोर करने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं भरत सिंह"

जयपुर, 22 जनवरी (का.प्र.)। अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्सेस पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेल के बीच अंतर्द्वंद चल रहा था। वहीं हाड़ौती में पहले ही कोटा में मंत्री शांति धारीवाल और लाडपुरा के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के बीच सीधा टकराव चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक भरत सिंह लगातार मंत्री प्रमोद जैन भाया पर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे, तो अब प्रमोद जैन भाया समर्थक दो विधायकों ने जवाबी हमला करते हुए भरत सिंह पर आरोप लगा दिया है कि, वे हाड़ौती में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

भाया समर्थक दो विधायक पानाचंद मेघवाल और निर्मला सहरिया ने भरत सिंह को कांग्रेस का जयचंद बताते हुए कहा है कि, भरत सिंह हाड़ौती में पार्टी को कमजोर करने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं। आपदिन अनावश्यक रूप से बारां में विरोध प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले प्रमोद जैन भाया समर्थक 2 विधायकों के खुलकर भरत सिंह के खिलाफ सामने आने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस

- इससे पहले शांति धारीवाल और नईमुद्दीन गुड्डू के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर हो ही चुकी है।
- भाया समर्थक विधायकों ने कहा, "जमीन से जुड़े कांग्रेसी ऐसी ओछी हरकतों से डरते नहीं हैं।"

की लड़ाई और खुलकर सामने आती दिख रही है। पिछले 1 सप्ताह से जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रदेश के दौर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयानों से सियासी पारा गर्म था। अब खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया और सांगोद विधायक भरत सिंह की अदावत तेज होती दिख रही है। भरत सिंह खान की झोपड़िया गांव को कोटा जिले में शामिल करवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि, वो आगामी 23 जनवरी को विधानसभा करेंगे।

भरत सिंह के इस बयान और बारां में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए भाया के समर्थक बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल और किसानगंज शाहबाद विधायक निर्मला सहरिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि, हाड़ौती में पार्टी को कमजोर करने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं। बिना वजह बारां में विरोध प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रहे है।

इससे पहले सांगोद विधायक भरत सिंह कई बार मंत्री भाया को प्रष्ट और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत पर दबाव बनाते रहे हैं। इसी के साथ लंबे समय से अलैच खनन, गोडावण, खान की झोपड़िया और सोरसन के मुद्दे को उठाते रहे हैं।

अब बारां अटरू के विधायक मेघवाल और निर्मला सहरिया ने संयुक्त बयान दिया है कि, हम विधायक भरत सिंह का सम्मान करते हैं। वे वरिष्ठ व पार्टी के पुराने नेता हैं। उन्हें और उनके परिवार को कांग्रेस से बहुत कुछ मिला है, लेकिन जब से बारां और कोटा अलग जिले से बने हैं, तभी से भरत सिंह बारां के कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे हैं। जिससे नेता के साथ ही पार्टी की छवि भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे उनकी कुंटा दिन-ब-दिन जाहिर हो रही है। साथ ही कहा है कि, भरत सिंह कई बार मुख्यमंत्री को लेकर भी भला बुरा कह चुके हैं। ऐसा

ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के साथ किया है।

दोनों विधायकों ने कहा है कि, भरत सिंह की यह हरकतें हाड़ौती और विशेष रूप से बारां जिले में कांग्रेस को कमजोर करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। बारां कांग्रेस के गढ़ खान की झोपड़िया गांव को कोटा जिले में मिलाने की कोई कोशिश भरत सिंह ने तब क्यों नहीं की, जब वे राज्य सरकार में मंत्री थे। अब यह निर्णय बारां जिले के स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है। इसके बावजूद यहां धरना प्रदर्शन कर माहौल खराब करने की ओछी हरकत कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। विधायक मेघवाल और सहरिया ने आरोप लगाया कि, बारां के विकास को रोकने के लिए इन्होंने सबसे पहले गोडावन मुद्दे को उठाया और अब खान की झोपड़िया के मुद्दे को उठा रहे हैं। यह आगे भी ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। हम बारां की जमीन से जुड़े कांग्रेसी ऐसी ओछी हरकतों से डरते नहीं हैं। ऐसे में अब हम भरत सिंह की इस ओछी हरकत और मानसिकता की निंदा करते हैं। भरत सिंह का यह कृत्य जयचंद जैसा व्यवहार करने की तरह है, लेकिन हम बारां के कांग्रेसी साहुल गांधी के नेतृत्व में देश-प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और भारत को जोड़ने की मुहिम में लगे रहेंगे।

चुनाव आयोग की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी

नई दिल्ली, 22 जनवरी (वार्ता)। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता के विषय पर इस सप्ताह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है।

यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जबकि भारत में अपने मूल स्थान से देश में ही दूसरी जगह

इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देश शामिल होंगे जो भारतीय चुनाव आयोग की कार्यशैली को जानने में विशेष रुचि रखते हैं।

पढ़ाई-लिखाई, रोजी- रोजगार के लिए रह रहे मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहां से अपने क्षेत्रों में वोट देने की सुविधा किए जाने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर विपक्ष ने आपत्तियां दर्ज की हैं।

विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में गड़बड़ी की आशंकाएं भी जाहिर करता रहा है।

निर्वाचन आयोग की वज्रपति के अनुसार यह सम्मेलन 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार करेंगे और समापन सत्र को निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पंडे संबोधित करेंगे।

भाजपा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रयास और अधिक स्पष्ट हो गए हैं। साथ ही मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आदिवासी समूहों और संघटनों के विरोध के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 और सिंगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन के प्रस्तावों को वापस ले लिया है।

साथ ही सरकार ने आदिवासी कल्याण पर बजटिय खर्च भी बढ़ाया और कृषि वानिकी तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया। मोदी सरकार उन दलित समुदायों को भी लुभा रही है जो कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं। गत 19 जनवरी को, उन्होंने उत्तरी कर्नाटक में रहने वाले लम्बानी खानाबदोश जनजातियों के 52,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को टाइटल डीड वितरित किए जो एक तरह का विश्व रिकॉर्ड था।

इन कोशिशों से भाजपा आदिवासी और दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भाजपा को कांग्रेस और जद (ए) के बीच मुस्लिम वोटों के बंटने से भी फायदा होने का भरोसा है।

भाजपा ने न केवल वृद्ध स्तर पर, बल्कि राज्य में सूक्ष्म स्तर पर भी आक्रामक चुनाव अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी बूथों पर संगठन को मजबूत करना है। इसके अलावा, यह विजय संकल्प अभियान यात्रा के माध्यम से घर-घर अभियान चलाने और लोगों से जुड़ने के उद्देश्य से चुनावी लाभांश प्राप्त करना चाहता है।

जहां तक कर्नाटक भाजपा के असंतुष्ट नेताओं का अनुसूच है, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, भाजपा उन्हें पार्टी की अभियान समिति में शामिल करके मनाने की रणनीति पर काम कर रही है।